नया क्या है !

यूनेस्को के साथ भारत के हालिया संबंध

अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन के पिछले सत्र के आउटगोइंग प्रेसीडेंट की हैसियत से तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह को 26 से 28 नवम्बर, 2008 तक जेनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन के 48वें सत्र का उद्घाटन करने हेतु आमंत्रित किया गया। माननीया मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी0 पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओलाबीयी बाबलोला जोसेफ भाई ने 2008 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरे से प्रेरित होकर उन्होंने 2011 में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ को मानवता के प्रति उनके योगदान को रेखांकित करने की दृष्टि से मनाने का प्रस्ताव किया जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

यूनेस्को में एक अन्य हाई प्रोफाइल कार्यक्रम हुआ जिसमें ओरोविले की 40वीं वर्षगाँठ की स्मृति में दिनांक 10 अक्तूबर, 2008 को ‘‘ओरोविलेः एन इमर्जिंग वर्ल्डः इट्स फ्यूचर हॉरिजन’’ विषय पर ओरोविले गोलमेज़ सम्मेलन के बाद ओरोविले नाटक ग्रुप द्वारा एक फ्यूजन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। दोनों कार्यक्रमों में एक हज़ार से भी अधिक व्यक्तियों ने शिरकत की। जिस सांस्कृतिक विविधता और बहुलता के लिए भारत एवं यूनेस्को सम्मान की बात की जाती है, उसको बढ़ाने के लिए ओरोविले एक महत्वपूर्ण अनुभव है।

कार्यकारी बोर्ड का 180 वाँ और 181वाँ सत्र

कार्यकारी बोर्ड का 180वाँ सत्र 30 सितम्बर से 21 अक्तूबर, 2008 तक आयोजित हुआ। मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ0 नवीन चन्द्र रामगुलाम ने इसे संबोधित किया जिसमें उन्होंने वैश्विक विरासत सूची में ‘‘अप्रवासी घाट’ लिखवाने के मॉरीशस द्वारा बढ़ाए गए महत्व को रेखांकित किया। इस लिखाई के लिए समर्थन देने हेतु उन्होंने भारत को भी धन्यवाद दिया। भारत ने सभी बोर्ड सदस्यों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया।

कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष की पहल पर सार्वभौमिक शांति और भाईचारे के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर, पाब्लो नेरुदा और ऐसे सिजेयर के योगदान को याद करने हेतु सर्वसम्मति से एक निर्णय को स्वीकार किया गया। 2011 में टैगोर की 150वीं वर्षगाँठ के सन्दर्भ में यह पहल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संकटापन्न भाषाओं के संरक्षण विषयक भाषा वर्ष तथा सभी के लिए शिक्षा के संवर्द्धन में भाषाओं की भूमिका के संदर्भ में आयोजित वस्तुपरक बहस में भी भारत ने अपने मुख्य वक्ता डा0 गणेश देवी के माध्यम से भाग लिया।

कार्यकारी बोर्ड का 181वॉं सत्र 14 से 30 अप्रैल, 2009 के दौरान आयोजित हुआ। इसके अलावा इस सत्र में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत की सदस्य डॉ0 कपिला वात्स्यायन, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग श्री आर0पी0 अग्रवाल और यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि सुश्री भास्वती मुखर्जी ने भी भाग लिया।

इस सत्र के दौरान गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती और 2010–2011 में मदर टेरेसा की 100वीं जयंती मनाने का भारत का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित हुआ। साथ ही, यूनेस्को की आगामी महासभा में वर्णानुक्रम में बैठने वाले देश का नाम बैलट बॉक्स से चुनने का उत्तरदायित्व सौंपते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने भारत की सदस्य डा0 कपिला वात्स्यायन को सम्मानित किया।

मुख्य कार्यक्रम–। : शिक्षा

भारत ने शिक्षा संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें 'कॉनफिन्टी–vi' (प्रिपेरेटरी कांफ्रेंस फॉर दी एशिया पेसिफिक रीजन) के साथ–साथ 26 से 28 नवम्बर, 2008 तक जिनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन के आउगोइंग प्रेसीडेंट थे, अतः भारतीय शिष्टमंडल की नेत्री श्रीमती डी0 पुरंदेश्वरी, माननीया मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री को 48वें अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने का सम्मान दिया गया। मुम्बई के आतंकी हमलों के साये में आयोजित इस सम्मेलन में भारत की सरकार और जनता के लिए शांति और शुभेच्छा का एक संदेश सर्वसम्मति से पारित किया गया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्रीमती डी0 पुरंदेश्वरी ने एकजुटता के इस संदेश के लिए सम्मेलन को यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभियान के लिए प्रतिबद्ध है।

दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया का उच्च शिक्षा पर उप क्षेत्रीय सम्मेलन

दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया का उच्च शिक्षा पर उपक्षेत्रीय तैयारी सम्मेलन (यूनेस्को के सहयोग से) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 और 26 फरवरी, 2009 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 14 देशों, नामतः अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, भारत, ईरान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, शिक्षाविद्, गैर–सरकारी संगठन, उच्च शिक्षा के नीति–निर्माता एवं पणधारियों ने भाग लिया।

सम्मेलन का उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा की गई।

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (उच्चतर शिक्षा) श्रीमती डी0 पुरंदेश्वरी, भूटान से माननीय मंत्री महामहिम ठाकुर सिंह पॉडियेल, मालदीव से माननीय मंत्री महामहिम डॉ0 मुस्तफ़ा लुत्फ़ी, मालदीव से माननीय राज्य मंत्री महामहिम डा0 अहमद अली मनिक, नेपाल से माननीया मंत्री महामहिम सुश्री रेणु कुमारी यादव, श्रीलंका से माननीय मंत्री महामहिम प्रो0 विश्व वर्णपाला और ईरान से मंत्री महामहिम डा0 मोहम्मद मेहदी जाहेदी ने इस समारोह की शोभा बढ़ाई।

5 से 8 जुलाई, 2009 को पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित सम्मेलन 'फेसिंग ग्लोबल एंड लोकल चैलेंजेज़ : द न्यू डायनामिक्स फॉर हायर एजुकेशन' उन क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला का एक हिस्सा था जो 'वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन हायर एजुकेशन' की भूमिका के रूप में आयोजित किए गए थे।

यह सम्मेलन वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर उच्च शिक्षा से जुड़े अनेक मुद्दों को रेखांकित करने में सफल रहा। इनमें मुख्यतः उच्च शिक्षा के संबंध में पहुँच, समानता, वित्तपोषण, शासन, गुणवत्ता आश्वासन और सतत विकास के मुद्दे शामिल थे। नई दिल्ली घोषणा का अंगीकरण इस सम्मेलन का नतीजा रहा जिसमें सहभागियों ने 'उच्च शिक्षा, राष्ट्र–निर्माण एवं सतत विकास के बीच बुनियादी संबंध की पुष्टि की और उपलब्ध संसाधनों में अभिवृद्धि हेतु विकल्प तलाशने की आवश्यकता पर बल देते हुए संवर्द्धित सार्वजनिक व्यय के जरिये उच्च शिक्षा के अवसरों के

विस्तार के प्रयास करने का संकल्प लिया। यह उच्च शिक्षा के लिए बढ़ती हुई सामाजिक माँग की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल देता है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों की और अधिक स्वायत्तता के साथ-साथ जवाबदेही में वृद्धि करते हुए गुणवत्ता के मानदंडों एवं पहुँच को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दोहराता है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि ''उच्च शिक्षा ऐसी विकासात्मक नीतियों का संवर्द्धन करने का साधन बनना चाहिए जो स्त्री-पुरुष संवेदी, आर्थिक रूप से वहनीय पर्यावरण के अनुकूल तथा मानवाधिकारों के प्रति सम्मान पर आधारित हों।''

मुख्य कार्यक्रम ।। : प्राकृतिक संसाधन

खेलों में डोपिंग के विरूद्ध समझौता

भारत खेलों में डोपिंग के विरूद्ध समझौते के सफल कार्यान्वयन में विशेष रुचि रखता है, विशेषकर तब जबकि भारत 2010 में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करेगा। इस समझौते में इस समय 105 राज्य पक्ष शामिल हैं। खेलों में डोपिंग के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय अभियान में भारत की प्रतिबद्धता के चलते भारत ने इंटरनेशनल फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स में 20,000 अमरीकी डॉलर का अंशदान किया है। भारत ने पूर्व में 7 नवम्बर, 2007 को इस समझौते का अनुसमर्थन किया था।

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु यूनेस्को कलिंग पुरस्कार

भारत ने यूनेस्को के विज्ञान कार्यक्रम का हमेशा दृढ़तापूर्वक समर्थन किया है। कलिंग पुरस्कार वर्ष 1951 में भारत सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था और तबसे यूनेस्को द्वारा प्रशासित किया गया है। कुछ कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता नोबल पुरस्कार कर चुके हैं जिनमें डा0 लुईस डी ब्रोगली, डॉ0 जॉर्ज पोर्टर, सरपीटर मेडावर और डॉ0 निकोलाई जी0 बोसोव शामिल हैं। बर्ट्रांड रसैल, कार्लवॉन फ्रिश और कॉनरेड लॉरेंज जैसे अन्य व्यक्तियों को बाद में नोबल पुरस्कार प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में यह एकमात्र पुरस्कार है। अगला पुरस्कार नवम्बर, 2009 में बुडापेस्ट में चौथे वर्ल्ड साइंस फोरम में प्रदान किया जाएगा।

जैव प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्रीय केंद्र

सरकार ने भारत में 99.55 करोड़ रू0 के संशोधित बजट के साथ जैव प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के एक क्षेत्रीय केंद्र (यूनेस्को के तत्वावधान में श्रेणी–2 संस्थान) की स्थापना का 20 नवम्बर, 2008 को अनुमोदन कर दिया। यह केंद्र जैव प्रौद्योगिकी में अंतरविषयक शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु एक क्षेत्रीय केंद्र होगा।

मानव तथा जीवमंडल कार्यक्रम

भारत यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के प्रारंभ से, इसके विकास में महत्तवपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले इस कार्यक्रम में 4 रिजर्व शामिल किए गए थे नामतः सुंदरबन, नंदादेवी, नीलगिरी जीवमंडल तथा मन्नार रिज़र्व के गल्फ 1 मई, 2009 में इसमें तीन और रिज़र्व नामतः नोकरेक जीवमंडल रिज़र्व (मेघालय), सिमलीपाल जीवमंडल रिज़र्व (उड़ीसा), पंचमढ़ी जीवमंडल रिज़र्व (मध्य प्रदेश) को भी इस सूची में शामिल किया गया है जिससे इनकी कुल संख्या 7 हो गई है।

मुख्य कार्यक्रम ।।। : सामाजिक और मानव विज्ञान

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 60वीं सालगिरह हेतु संस्मारक कार्यकलाप

10 दिसम्बर, 1948 को यूएन सामान्य सभा द्वारा अभिग्रहित मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के मूल हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने इसकी 60वीं वर्षगाँठ के वर्ष भर चलने वाले उत्सव में भाग लिया था। इन कुछ कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैः

* 8 से 10 दिसम्बर 2008 तक यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित ‘‘मानव अधिकार शिक्षा के 60 वर्ष’’ शीर्षक से आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया जिसकी काफी प्रशंसा की गई। इस उत्सव के लिए प्रदर्शित वस्तु रा.शै.अ.प परिषद, और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रदर्शित किए गए थे तथा इनसे मानव अधिकार शिक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया था।

* 3 दिसम्बर, 2008 को यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में नॉन एलाईंग मूवमेंट द्वारा मानव अधिकार और सांस्कृतिक विविधता पर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारत ने इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक विविधता और इसके प्रति सम्मान पोषित करने हेतु शिक्षा एक अच्छा तंत्र था।

अंतर्राष्ट्रीय जैव नैतिकता समिति और अंतर्शासकीय जैव नैतिकता समिति

भारत ने अपने विशेषज्ञ, प्रोफेसर एच.शरत चंद्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जैव–नैतिकता समिति में प्रतिनिधित्व किया। भारत अंतर्शासकीय जैव–नैतिकता समिति का सभी सदस्य है। सामाजिक उत्त्रदायित्व और स्वास्थ्य तथा क्लोनिंग और गवर्नेंस पर आईबीसी के कार्यो की प्रोन्नति पर चर्चा के लिए 30–31 दिसम्बर, 2008 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में दो समितियों का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था। भारत सामाजिक उत्तरदायित्तव और स्वास्थ्य पर आई बी सी कार्यदल का भी सदस्य है।

<u>मुख्य कार्यक्रम IV: संस्कृति</u>

विश्व परंपरा समिति का 32वां सत्र

विश्व परपंरा सम्मेलन में स्टेट पार्टी के रूप में भारत ने 2–10 जुलाई, 2008 को क्योवेक कनाडा में आयोजित/विश्व परंपरा समिति के 32वें सत्र में भाग लिया। जिन्होंने भारत में पर्वतीय रेल का विस्तार कालका शिमला रेल पर हमारे नामज़दगी को अनुमोदित किया।

भारत हेरिटेज साईट के लिए अस्थायी सूची में नालंदा जैसे अन्य स्थलों को शामिल करने के भी प्रयास कर रहा है। अस्थायी सूची के इन स्थलों पर तद्न्तर वर्ल्ड हेरिटेज़ कमेटी द्वारा इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

4 से 8 नवम्बर, 2008 तक इस्तनबुल, तुर्की में अतिसूक्ष्म सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु समिति का तीसरा असाधारण सत्र।

इस बैठक का प्रयोजन अतिसूक्ष्म सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए संचलनात्मक निर्देश विकसित करना था। ये सांस्कृतिक विरासत, इसकी सुरक्षा हेतु आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय यंत्र के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करने में सहायता मिलेगी। चूँकि उप राष्ट्रपति एशिया पेसिफिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अतः बैठक में चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

एक महत्तवपूर्ण पहल थी– मानवता की अतिसूक्ष्म सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना। वेदिक गुणगान और रामलीला की परंपरा कुटीयाट्टम (संस्कृत थियेटर) भारत के रामायण के पारंपरिक निष्पादन को इस सूची में शामिल किया गया है। कई भारतीय गैर–सरकारी संगठन जैसे भारतीय लोक कला मंदिर, संस्कृति

प्रतिष्ठान तथा वृंदा कथक केन्द्र को भारत द्वारा समर्थन के कारण प्रत्यायन प्राप्त करने में सफलता मिली है।

अतिसूक्ष्म सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु सम्मेलन के लिए स्टेट पार्टीज की सामान्य सभा का दूसरा सत्र

अतिसूक्ष्म सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु सम्मेलन के लिए स्टेट पार्टीज की सामान्य सभा का दूसरा सत्र 16–19 जून, 2008 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित किया गया था। भारत का ब्यूरो के लिए एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र से चयन किया गया था।

24 सदस्यीय अंतर्शासकीय समिति के चुनाव हेतु फलोटींग सीट की सहभागिता के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र और अरब ग्रुप के बीच बातचीत में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई स्टेट पार्टीज़ ने दिल्ली में (2–4 अप्रैल, 2007) सम्मेलन पर विशेषज्ञ बैठक आयोजित करने के लिए भारत की सराहना की। इस बैठक में सचलनात्मक निर्देशों के प्रारूपण से संबंधित सारवान मुद्दों पर चर्चा की गई।

सांस्कृतिक विविधता संबंधी समिति का पहला असामान्य सत्र, पेरिस दिनांक 24 से 27 जून, 2008 और समिति का दूसरा सामान्य सत्र, पेरिस दिनांक 8 से 12 दिसम्बर 2008

भारत ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की विविधता की सुरक्षा और संवर्धन संबंधी समझौता तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और वह दिसम्बर, 06 में समझौतों का समर्थन करने वाला विश्व में 22वां देश और एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहला देश था।

दोनों बैठकों का उद्देश्य ऐसे संचालनात्मक दिशा–निदेर्शों के जरिए समझौते को संचालित करना था जिन्हें जून, 2009 में राज्य पक्षों के सम्मेलन द्वारा अपनाया जाएगा। भारत ने दोनों बैठकों के लिए ब्यूरो में एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और विचार–विमर्शो में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विकासशील देशों के लिए वरीयता व्यवहार से संबंधित समझौते के अनुच्छेद 16 के संचालन में भारत की भूमिका इस समझौते की सफलता में अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16 में विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को स्वैच्छिक रूप से वरीयता व्यवहार प्रदान करके सांस्कृतिक विविधता बनाए रखने में योगदान देकर सांस्कृतिक विविधता के संवर्धन और सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। इस क्षेत्र

में भारत सांस्कृतिक विविधता कोष में स्वैच्छिक अंशदान देने वाले देशों में से एक है। भारत ने इस कोष में 6,81,504/- रूपए की राशि का अंशदान दिया है।

उद्गम देश में सांस्कृतिक सम्पदा की वापसी के संवर्धन हेतु अंतर सरकारी समिति का असामान्य सत्र

उद्गम देश में सांस्कृतिक सम्पदा की वापसी के संवर्धन हेतु अंतर सरकारी समिति का असामान्य सत्र 25-28 नवम्बर, 2008 में सीओल, कोरिया गणराज्य में आयोजित किया गया था। इस बैठक में समिति की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ का स्मरणोत्सव भी मानाया गया। भारत ने हमेशा इस मामले में सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाया है। सांस्कृतिक वस्तुओं चाहे वे युद्ध अथवा औपनिवेशिक समय में विस्थापित हों को उद्गम देश में वापस कर दिया जाना चाहिए। भारत ने ''विश्व युद्ध ।। के संबंध में विस्थापित सांस्कृतिक वस्तुओं से संबद्ध सिद्धांतों की घोषणा'' का मसौदा तैयार करने में भागीदारी की है और वह इस मसौदा घोषणा को अपनाने के लिए वार्तालापों में सुसाध्य भूमिका निभाता रहा है।

<u>प्रमुख कार्यक्रम V: दूरसंचार और सूचना</u>

दूरसंचार विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण यूनेस्को कार्यक्रम है जहाँ भारत के स्वैच्छिक 30,000 अमरीकी डालर के अंशदान की काफी सराहना की जाती है। भारत साइबरस्पेस में बहुभाषाओं के प्रयोग के संवर्धन में सक्रिया भूमिका निभाता रहा है। तीसरा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईजीएफ 3 से 6 दिसम्बर 2008 तक हैदराबाद में आयोजित किया गया था। आईजीएफ में यूनेस्को ने ''साइबरस्पेस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ''इंटरनेट फिल्टरिंग और सेंसरशिप'' तथा विकासशील पहलु के साथ सार्वजनिक सूचना तक पहुँच'' संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया। वर्ष के दौरान, यूनेस्को के साथ भारत की पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय मिशन ने भारत तथा अन्य दक्षिण एशियाई देशों से संबंध दस्तावेजी परंपरा तक समान पहुँच का संवर्धन करने के लिए नीति अवसंरचना और नयाचार के विकास में सहायता देने हेतु ''दस्तावेजी परंपरा तक समान पहुँच के संवर्धन हेतु कानूनी और नीति अवसंरचना'' शीर्षक का एक अनुसंधान अध्ययन पूरा किया है।

ओरोविले फाउंडेशन

ओरोविले की स्थापना श्री अरविंदों की अनुयायी 'माँ' द्वारा 28 फरवरी 1968 को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पदुचेरी के बाहरी छोर पर एक अंतराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में की गयी थी जहाँ वर्तमान भारत सहित 43 देशों के

लगभग 2007 लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं और स्वयं को सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और मानव एकता के उद्देश्य से अन्य खोज में लगाते हैं।

यूनेस्को ने 1968 में पारित एक संकल्प द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों को ओरोविले को एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप जिसे ऐसे जीवन मानकों के साथ विभिन्न मूल्यों को परस्पर इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है जो मानव की भौतिक तथा अध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसकी ओरोविले के 4 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार व्याख्या की गयी है, के रूप में विकसित करने में भागीदारी हेतु आमंत्रित किया था।

यह टाउनशिप 1980 से मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और इसे ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार शासित किया गया है।

ओरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार प्रतिष्ठान में (क) एक अधिशासी बोर्ड; (ख) निवासियों की एक सभा; (ग) आरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (आईएसी) शामिल है। 9 सदस्यों वाले अधिशाससी बोर्ड को अक्टूबर, 2008 में 4 वर्ष के लिए पुनर्गठित किया गया।

आरोविले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आरोविले स्थापना अनुरक्षण और योजनागत तथा योजनेतर अनुदानों के अधीन आरोविले के विकास संबंधी खर्च वहन करने के लिए प्रतिष्ठान को भारत सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है। योजनागत के तहत वर्ष 2008–09 के लिए 570.00 लाख रूपए और योजनेतर के लिए 127.00 लाख रूपए जारी किए गए हैं।

श्री अरबिंदो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल रिसर्च तथा भारत निवास की निर्माण गतिविधियों के अतिरिक्त फाउंडेशन ने वर्ष के दौरान 'स्वागतम' अतिथि गृह का निर्माण तथा श्री अरविंदो आडिटोरियम के उन्नयन का कार्य किया है। फाउंडेशन ने एक बड़े स्तर पर आरोविले की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मनाई है।